acquired without Government assistance, the company may be allowed to sell such ship as per its commercial judgement;

(ii) Director General of Shipping/ Shipping Credit and Investment Company of India is satisfied about the reasonableness of the price;

(iii) the sale proceeds after meeting outstanding liabilities of Shipping Credit and Investment Company of India/Government/ Financial institutions, etc. are kept in a separate account for shipowner to be used only for acquisition of further ships.

(d) During the last one year, Government accorded permission for 4 such ships to be sold.

Property Tax Bills in Respect of DDA Flats in Vasant Kunj, New Delhi

3331. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that DDA flats in Vasant Kunj area particularly in Sector-D have been allotted and occupied since 1988 but the Municipal Corporation of Delhi has not so far assessed their rateable value and issued property tax bills;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government propose to expedite the assessment; and

(d) if so, by when the property tax bills would be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (d) Property tax notices regarding properties completed or occupied after 1.4.1988 have not been issued so far. However, the tax-payers were permitted to pay taxes according to their self-assessment. The process of issue of notices for assessment of these properties shall be completed before 31st March, 1991.

Passport Office in Goa

3332. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the present Passport Office in Goa is inadequate and that there is a demand for larger centrally located space for its offices; and

(b) if so, by when Government propose to shift this office to the new premises and the location thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI HARI KISHORE SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Negotiations for hiring alternative accommodation near the existing permises are under way.

त्रिपुरा में धर्म-परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया जाना

3333. श्री राम जेठमलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1990 के दैनिक "हिन्दू" में "कनवर्शन टू क्रिश्चेनिटी राइजिंग इन त्रिपुरा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या न्यूजीलैंड बैपटिस्ट मिशन सोसाइटी ने गत छः वर्षों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्म-परिवर्तन किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्यतः धर्म-परिवर्तन आदिवासियों को विभिन्न प्रलोभन देकर कराये गये थे ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस सोसाइटी को गत कुछ वर्षों के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; यदि हां, तो इस सोसाइटी को गत तीन वर्ष के दौरान विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 1987 से 1989 की अवधि के दौरान न्यूजीलैंड बैपटिस्ट मिशन सोसाइटी, न्यूजीलैंड, से जुड़ी हुई त्रिपुरा बैपटिस्ट क्रिश्चयन यूनियन ने लगभग 8000 हिन्दुओं (अधिकांश आदिवासी) को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने की सूचना मिली है।

(ग) जबकि इस आशय के कोई समाचार नहीं है कि जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है उनको नकद लाभांश दिए गए हैं लेकिन उन्हें खाना, दवा कपड़ा और शिलोंग में उच्च शिक्षा दिलवाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिन्होंने इसाई धर्म अपना लिया है।

(घ) त्रिपुरा में त्रिपुरा बैपटिस्ट क्रिश्चियन यूनियन ने वित्तीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशि प्राप्त की है :—

वर्ष	राशि
	ल ख
1987 . .	4.38
1988 . .	7.23
1989 . .	7.85

वाणिज्यिक उपयोग के लिए दूरभाष प्रभारों को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

3334. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूरभाष शुल्क की विभिन्न दरें विहित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या व्यापारिक उपयोग के लिए दूरभाष प्रभारों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सामाजिक और धार्मिक प्रयोजनों के लिए दूरभाष प्रभारों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार विभिन्न जातियों के आधार पर बने विभिन्न वर्गों (पिछड़े और उच्च वर्ग) द्वारा दूरभाष के इस्तेमाल के लिए शुल्क की विभिन्न दरें विहित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्तमान में शुल्कों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आवासीय और गैर-आवासीय उपभोक्ताओं के लिए पृथक शुल्क निर्धारित कर के औचित्य पर तभी विचार किया जाएगा जबकि इसमें संशोधन करना आवश्यक हो।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

देश में दूरभाष उपकरणों का निर्माण

3335. **श्री राम जेठ मलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूरभाष उपकरणों के निर्माण के लिए औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में दूरभाष में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री और उपकरणों के निर्माण में आत्म निर्भर बनने के लिए समय संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के प्रत्येक गांव के दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ; और